विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक बहुपक्षीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए वैश्विक नियम निर्धारित करता है। संगठन के 166 सदस्य हैं जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 फरवरी से 1 मार्च, 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हर दो साल में एक बार आयोजित किया जाता है और यह संगठन में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है।

वैश्विक व्यापार में इसके आर्थिक महत्व को देखते हुए भारत इस संगठन का एक प्रमुख सदस्य रहा है। यह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में आवश्यक विकास परिप्रेक्ष्य को सामने रखता रहा है जिसे दोहा विकास कार्यसूची का आधार माना जाता था। इसने विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए पद संभालने की अपनी जिम्मेदारी से परहेज नहीं किया है। इसके लिए राजनेता कौशल और

विकसित देशों द्वारा डाले गए भारी दबाव को झेलने की क्षमता की आवश्यकता है।

13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कई मुद्दे चर्चा के लिए आये और भारत विकासशील देशों की स्थिति को स्पष्ट करने में कामयाब रहा। प्रमुख मुद्दे कृषि, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, अल्प विकसित देश (एलडीसी), निवेश सुविधा आदि पर थे। हालाँकि, केवल ई-कॉमर्स अधिस्थगन और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स) छूट पर एक समझौता था। कैमरून में अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के मद्देनजर अन्य मुद्दों पर जिनेवा में वार्ता समितियों में काम किया जाएगा।

माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारत ने विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के साथ-साथ 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में परिणाम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की वार्ता दल में वाणिज्य सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के राजदूत और वाणिज्य विभाग (टीएनएम डिवीजन) के साथ-साथ भारत के स्थायी मिशन के अधिकारी शामिल थे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अध्ययन केंद्र, जो कि प्रबुद्ध मंडल है, ने इस वार्ता टीम का समर्थन किया।

वार्ता के दौरान जिन प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई उनमें से कुछ निम्नलिखित थे:

i. कृषि

जहां तक विकास के आयाम का सवाल है यह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। भारत और उसका गठबंधन जिसे जी-33 कहा जाता है, खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर एक परिणाम पर बातचीत कर रहे थे। हालाँकि, विडंबना यह है कि उन देशों ने इसका काफ़ी विरोध किया जो सबसे अधिक सब्सिडी प्रदान करते हैं। मुख्य मुद्दा भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसे प्रशासित मूल्य तंत्र के मामले में सब्सिडी की गणना में इस्तेमाल की जाने

वाली पद्धति थी। कृषि पर समझौते के हिस्से के रूप में प्रशासित मूल्य को ऐतिहासिक मूल्य (1986-88 का औसत) के विरुद्ध बेंचमार्क किया गया है। हालाँकि, खाद्य मुद्रास्फीति के कारण, कृत्रिम रूप से गणना किया गया यह सब्सिडी स्तर उच्च हो जाता है और न्यूनतम स्तर का उल्लंघन करता है। यह त्रुटिपूर्ण गणना पद्धति ही है जो भारत जैसे विकासशील देशों की एमएसपी रखने में असमर्थता के मूल में है। हालाँकि, चूंकि बाली में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान शांति खंड पर बातचीत हुई थी, इसलिए कोई भी किसी देश को इस पर विवाद में नहीं ले जा सकता। आश्चर्य की बात नहीं कि दुनिया भर के सब्सिडीदाताओं ने इस मुद्दे पर किसी भी स्थायी समाधान पर आपत्ति जताई।

सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम

- खाद्य सुरक्षा और घरेलू खाद्य सहायता के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग तकनीकी रूप से हरे पेटी में है
- हालाँकि, यदि खाद्य प्रशासित कीमतों (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जाता है, तो सब्सिडी घटक को अधिसूचित किया जाना चाहिए
- हालाँकि, यदि खाद्य प्रशासित कीमतों (भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर खरीदा जाता है, तो सब्सिडी घटक को अधिसूचित किया जाना चाहिए
- बाजार मूल्य समर्थन की गणना एक निश्चित बाहरी संदर्भ मूल्य और लागू प्रशासित मूल्य के बीच के अंतर को लागू प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए योग्य उत्पादन की मात्रा से गुणा करके की जाती है।

एमपीएस = (एएपी-ईआरपी)*क्यू

जहाँ,

- 'एमपीएस'- बाजार मूल्य समर्थन है
- 'एएपी'- अनुप्रयुक्त प्रशासित मूल्य है
- ईआरपी- बाहरी संदर्भ मूल्य है (वर्ष 1986-88 के लिए)
- 'क्यू'- लागू प्रशासित मूल्य प्राप्त करने के लिए योग्य उत्पादन की मात्रा है

इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि कृषि पर समझौता संभवतः सबसे विषम समझौतों में से एक है क्योंकि अधिकांश विकसित देश अपने मौजूदा सब्सिडी कार्यक्रमों को अलग करने के लिए बातचीत करने में कामयाब रहे। ये हरे बॉक्स और नीले बॉक्स का हिस्सा हैं, बाद वाले वे हैं जहां उत्पादन को सीमित करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। हालाँकि, कुछ विकसित देशों ने अपने सब्सिडी

कार्यक्रमों में सुधार किया है, वे इन्हें क्रमशः स्वीकार्य हरे और नीले बॉक्स में रखने में सक्षम हैं।

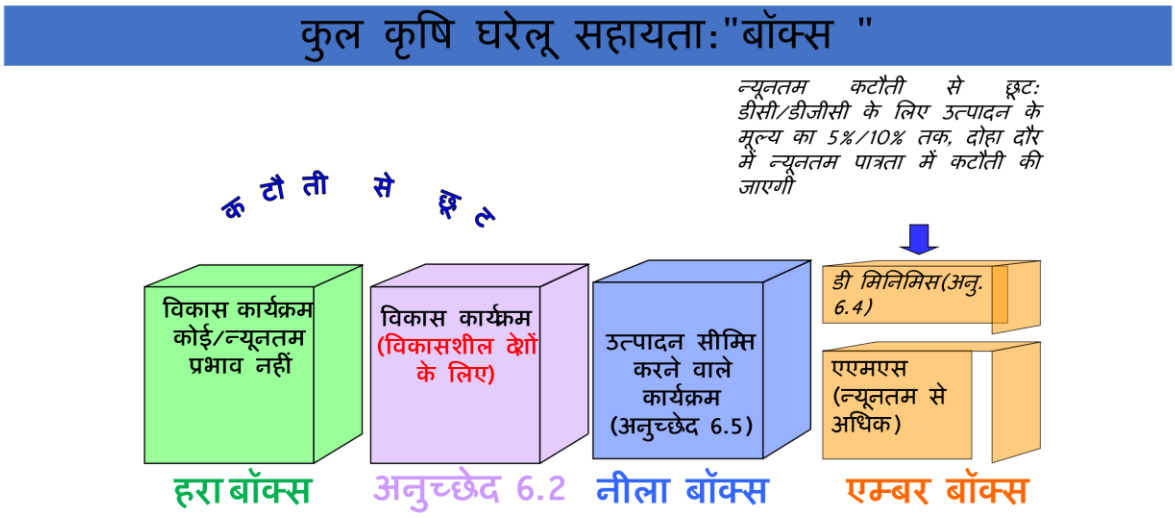

घरेलू सहायता के मुख्य उपयोगकर्ता - डीसी; विकासशील देशों के पास बजट की कमी है

खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के मुद्दे के अलावा, घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच, निर्यात निषेध/प्रतिबंध/प्रतिस्पर्धा और कपास के क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई। घरेलू समर्थन और बाज़ार पहुंच से संबंधित मुद्दों पर यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे विकसित देशों के बीच भी मतभेद थे। इसलिए, कोई समझौता नहीं हो सका और यह महत्वपूर्ण स्तंभ इस मंत्रिस्तरीय बैठक में अनिर्णायक रहा।

ii. द्मत्स्य पालन सब्सिडी

जून 2022 में हुए समझौते में समझौते के दो स्तंभों को शामिल किया गया, अर्थात् अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना और अत्यधिक मात्रा में मछली पकड़ना। यह समझौता क्षेत्राधिकार के बाहर मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर भी रोक लगाता है। समझौते में विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के उपाय हैं। लाभ प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों के लिए अधिसूचना और पारदर्शिता आवश्यकताएँ मौजूद हैं। आपदा राहत के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए अवसर की एक खिड़की मौजूद है। अंत में, यह कहा गया है

कि समझौते के चार वर्षों के भीतर व्यापक विषयों को विकसित करने की आवश्यकता है अन्यथा इसे समाप्त कर दिया जाएगा।

एमसी13 में उद्देश्य अत्यधिक क्षमता और अत्यधिक मछली पकड़ने के तीसरे स्तंभ को देखना था। हालाँकि, मतभेद के प्रमुख क्षेत्र उच्च समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रदान की जाने वाली सब्सिडी और कारीगर मत्स्य पालन के लिए विशेष और विभेदक उपचार की अपर्याप्तता थे। कई विकसित देश गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं और इस पर कोई अनुशासन नहीं चाहते हैं। यहां तक कि चीन जैसे देशों के पास भी गहरे समुद्र में अपने बेड़े हैं, जहां उनके कर्मचारी तैनात रहते हैं। कारीगर मत्स्य पालन पर, ये उन मछुआरों से संबंधित हैं जो आजीविका के साधन हैं और मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। इसलिए सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त समयावधि प्रदान करना महत्वपूर्ण है। बड़े मछली पकड़ने वाले देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी, विषय पर चर्चा की गई और आगे की बातचीत के लिए इसे लिया जाएगा।

iii. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर 1997 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का एक कार्य कार्यक्रम था। ऐसे कई क्षेत्र थे जिन पर चार मंचों पर बातचीत होनी थी। हालाँकि, इसमें बहुत कम प्रगति हुई और यह मंत्रिस्तरीय अगले मंत्रिस्तरीय तक समयसीमा के साथ काम जारी रखना चाहता है। ई-कॉमर्स अधिस्थगन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने के बारे में है। हालाँकि स्थगन की सटीक प्रकृति पर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन एक सामान्य समझ है कि यह इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों या पत्रिकाओं से संबंधित है। कुछ अध्ययनों ने राजस्व हानि की मात्रा का संकेत दिया है, हालांकि यह भी एक तथ्य है कि देश ऐसे ट्रांसमिशन पर कोई शुल्क नहीं लगाते हैं या लगाने की कोई ठोस योजना नहीं है। मंत्री इस रोक को बढ़ाने पर सहमत हुए।

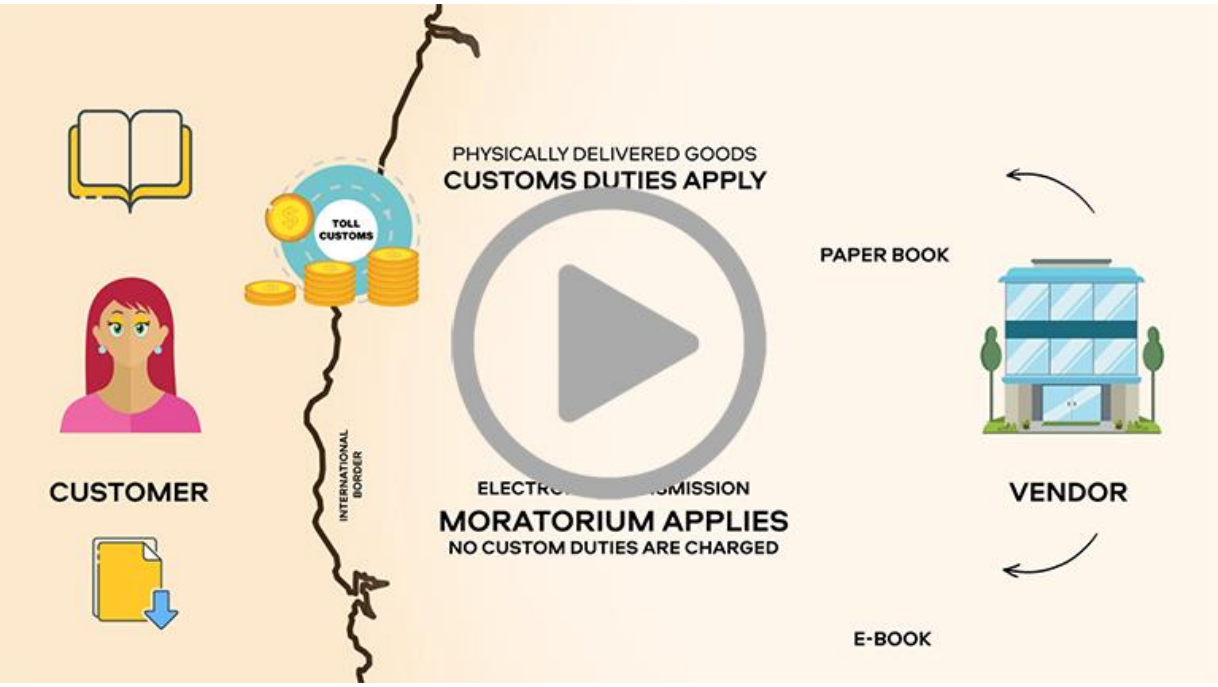

iv. बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स)

बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स) विश्व व्यापार संगठन में बौद्धिक संपदा से संबंधित समझौता है। मंत्रिस्तरीय बैठक में उठाए गए मुद्दों में से एक गैर-उल्लंघन और स्थितिजन्य शिकायतों का था। ये ऐसी शिकायतें हैं जो ट्रिप्स के कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करती हैं लेकिन व्यापार में बाधाएं पैदा करने के अर्थ में समझौते की भावना के खिलाफ हैं। इसे हमेशा ई-कॉमर्स अधिस्थगन से जोड़ा गया है और यहां तक कि इस मंत्रिस्तरीय बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि सदस्य ऐसी शिकायतें शुरू नहीं करेंगे।

v. बहुपक्षीय समझौते

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सर्वसम्मति आधारित दृष्टिकोण के कारण धीमी प्रगति के कारण, कुछ देशों ने बहुपक्षीय समझौतों पर विचार करने का निर्णय लिया। इन समझौतों में देशों का एक समूह किसी सामान्य मुद्दे पर एक साथ आता है और सदस्यता बढ़ाने का प्रयास करता है। इन्हें संयुक्त वक्तव्य पहल या जेएसआई के रूप में संदर्भित किया गया था और इसमें घरेलू विनियमन,

एमएसएमई, लिंग, स्थिरता, निवेश सुविधा आदि जैसे कई क्षेत्रों को शामिल किया गया था।

13वीं मंत्रिशास्त्रीय बैठक के दौरान बहुप्रतीक्षित बैठकों में एक निवेश सुविधा थी। भारत ने पुरातनपंथी के रूप में इसका विरोध किया क्योंकि इस समूह को ऐसे सामान्य उत्साह को उठाने की हिस्सेदारी के आधार पर संगठन के बहुपक्षीय निर्णय को प्रभावित करना पड़ा, जिससे बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त होगा। निवेश इकाई को लगभग 123 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था और चिली तथा कोरिया इस प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे थे।

मंत्रिस्तरीय बैठक में उल्लेखित कुछ अन्य बहुपक्षीय समझौते प्लास्टिक प्रदूषण और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ प्लास्टिक व्यापार (डीपीपी) से संबंधित थे, जिन्हें 78 सदस्यों व्यापार और पर्यावरणीय स्थिरता संरचित चर्चाएँ (TESSD) का समर्थन प्राप्त था; जिसे कनाडा और कोस्टा रिका के समन्वयक 48 सदस्यों के साथ जीवाश्म ईंधन सब्सिडी सुधार (एफएफएसआर); और 72 सदस्यों के साथ सेवा घरेलू विनियमन में अच्छे नियामक अभ्यास का कार्यान्वयन के साथ 76 सदस्यों का समर्थन प्राप्त था।

निष्कर्षतः, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) वार्ता निश्चित रूप से धीमी हो गई है। हालाँकि, यह संभावना है कि बातचीत इसी गति से जारी रहेगी और प्रत्येक मंत्रिस्तरीय वार्ता के नतीजे केवल कमजोर ही होंगे। कुछ देश स्थिरता, पर्यावरण, श्रम, जलवायु परिवर्तन, लिंग आदि जैसे गैर-व्यापार मुद्दों को कार्यसूची का हिस्सा बनाने पर जोर देते रहेंगे। इन्हें विकासशील देशों से निर्यात के विरुद्ध बाधाएँ खड़ी करने के उपकरण के रूप में बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। धीमी प्रगति के बावजूद भारत बहुपक्षीय प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध रहा है। यह हमेशा संतुलित, समतापूर्ण और विकासोन्मुख परिणाम के लिए खड़ा रहा है।

****